IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

विकसित भारत @2047: प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में

राजा राम (शोधार्थी)

शिक्षाशास्त्र विभाग

लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश

सारांश

इस अध्ययन में यह समझने का प्रयास किया गया है कि एक मजबूत और सबको साथ लेकर चलने वाली शिक्षा प्रणाली विशेषकर प्राथमिक शिक्षा, कैसे हमारे देश को विकसित बनाने में योगदानपरक साबित हो सकती है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखने का जो सपना है, उसमें प्राथमिक शिक्षा की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा को, शिक्षा की आधारशिला मान जाता है। इस अध्ययन में यह समझने का प्रयास किया गया है कि, स्कूलों में पढ़ाई का स्तर, अध्यापक प्रशिक्षण, डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल और अन्य मूलभूत आवश्यकताएँ किस प्रकार अधिगमकर्ता के सीखने पर असर डाल रही हैं और यदि शिक्षा के इस स्वरुप में परिवर्तन नहीं हो पाया तो भारत के विकसित राष्ट्र बनने तक या उसके बाद भारत में प्राथमिक शिक्षा का क्या स्वरुप हो सकता है। और वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा में किस प्रकार के प्रमुख बदलाव किये जाएँ कि, प्राथमिक शिक्षा भारत को विकसित और मजबूत राष्ट्र बनाने में सर्वाधिक योगदान दे सके। इस अध्ययन में शोध विधि के रूप में 'सामग्री विश्लेषण' (Content Analysis) का प्रयोग किया गया है।

मुख्य शब्द : प्राथमिक शिक्षा, विकसित भारत, अध्यापक प्रशिक्षण, डिजिटल उपकरण, ई-लर्निंग।

प्रस्तावना

भारत जैसा देश जहाँ संस्कृति, भाषा, और सोच की इतनी विविधता है, वहाँ शिक्षा सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं होती अपितु यह तो बच्चे के मन, सोच और व्यवहार की नींव रखती है और उस पर एक विशाल इमारत को स्थापित करने में सहयोग प्रदान करती है। प्राथमिक शिक्षा, पढ़ाई, वो पहला पड़ाव होता है जहाँ एक बच्चा स्कूल जाना सीखता है, दुनिया को देखना शुरू करता है इसलिए यदि हम "विकसित भारत" की बात करते हैं, तो सबसे पहले ध्यान इसी ,मुद्दे पर जाना चाहिए।

आज के समय में भारत की प्राथमिक शिक्षा ने कई स्तरों पर तरक्की की है जैसे स्कूलों की संख्या बढ़ी है, योजनाएँ लागू हो रही हैं (मिड-डे मील, समग्र शिक्षा, पढ़े भारत जैसी योजनाएँ)। लेकिन सच्चाई ये भी है कि अभी भी बहुत से गाँवों में स्कूलों की हालत कुछ खास नहीं है, टीचर्स कम हैं या वो खुद तैयार नहीं हैं। यही सब देखते हुए इस अध्ययन का एक उद्देश्य यह है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति को समझा जाए और जो कठिनाइयाँ हैं, उन्हें पहचाना जाए तथा उसमे सुधार करके भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में यथासम्भव सहयोग किया जाय।

यदि हमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो शिक्षा को तो बिल्कुल नए रंग में ढालना होगा। सिर्फ किताबें और अंकपत्र के अलावां भी शिक्षा के सन्दर्भ में विचार होना चाहिए जो बच्चे को सोचने, समझने और कुछ नया करने की क्षमता और योग्यता प्रदान करे। इसी सन्दर्भ अध्ययन का एक उद्देश्य यह भी है कि, हम इस बात को समझ पायें कि विकसित भारत में प्राथमिक शिक्षा का चेहरा कैसा होगा? किन्तु यह सिर्फ कल्पना की बात नहीं है बल्कि इसके लिए हमें आज की शिक्षा व्यवस्था में कुछ गहरे बदलाव करने होंगे। इसीलिए इस अध्ययन का एक उद्देश्य यही भी है कि, यह देखा जाए कि कौन-कौन से सुधार प्राथमिक शिक्षा में अभी किए जाएँ ताकि वो 2047 तक देश की रीढ़ बन सके।

अध्ययन के उद्देश्य

1 भारत में प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति एवं चुनौतियों का अध्ययन करना।

2 विकसित भारत में प्राथमिक शिक्षा के संभावित स्वरूप का विश्लेषण करना।

3 विकसित भारत में योगदान हेतु वर्तमान प्राथमिक शिक्षा में आवश्यक कुछ प्रमुख सुधारों का अध्ययन करना।

भारत में प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति एवं चुनौतियाँ

UDISE Plus (Unified District Information System for Education plus) रिपोर्ट के अनुसार, 'भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक है, जिसमें लगभग 14.72 लाख स्कूल, 98 लाख से अधिक शिक्षक और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आधारभूत से माध्यमिक स्तर तक लगभग 24.8 करोड़ छात्र हैं। यह प्रणाली देश भर में मानकों और एकरूपता को बनाए रखने का प्रयास करती है, जबकि देश की विविध संस्कृति और विरासत को बढ़ने और फलने-फूलने के लिए पर्याप्त गुंजाइश देती है'।[1]

संसाधनों की कमी

भारत में प्राथमिक शिक्षा की हालत देखकर समझ आता है कि संसाधनों की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है। कई सरकारी स्कूलों में आज भी बच्चों के लिए न तो उपयुक्त शौचालय हैं, न ही साफ पानी या बिजली। इसके अलावा, टीचर्स की संख्या भी कम है। स्कूलों में खेल कूद, पुस्तकालय जैसी बुनियादी सुविधाएँ भी उचित रूप में नहीं मिल पातीं। इससे बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आती है, और उनका विकास सही ढंग से नहीं हो पाता। **ASER** (Annual Status of Education Report) पर गौर करें (Figure 1) तो 2010 से 2024 तक कई मूलभूत सुविधाओं के प्रतिशत में में बढ़ोत्तरी हुयी है किन्तु कम्प्यूटर की उपलब्धता और उपयोग के सन्दर्भ में यह बढ़ोत्तरी न के बराबर कही जा सकती है। जब भी हम संसाधनों की कमी की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सरकारी स्कूलों की ओर जाता है किन्तु यह संख्या भी कहीं ज्यादा है। इस सन्दर्भ में असर रिपोर्ट का आँकड़ा इस प्रकार है-

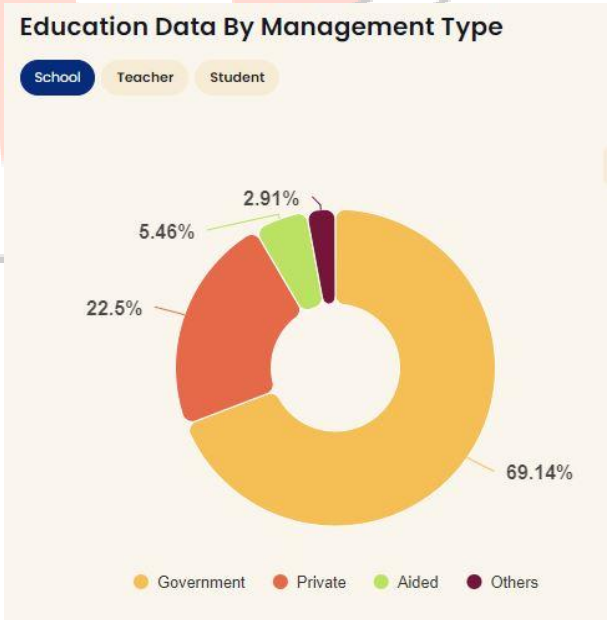

Figure 1

प्रशिक्षण का अभाव एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की कमी

टीचर्स को अच्छे तरीके से ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, जिससे उनकी पढ़ाने की विधि भी ठीक से परिस्कृत नहीं हो पाती। कुछ टीचर्स शिक्षा में नवाचार और तकनीक से अनजान रहते हैं, जो बच्चों के लिए ज़रूरी हैं। प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की कमी भी एक प्रमुख समस्या है। ज्यादातर शिक्षक अभी भी पारंपरिक तरीकों से ही पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों रूचि नहीं उत्पन्न होती है। ऊपर से, शिक्षक-छात्र का अनुपात भी बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों को व्यक्तिगत ध्यान देने में भी परेशानी आती है। इस वजह से बच्चे सही तरीके से पढ़ नहीं पाते, और उनकी शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। गुणवत्ता के सन्दर्भ में असर रिपोर्ट का यह आंकड़ा (Table 1) भी ध्यान देने योग्य है।

विद्यालय प्रकार के अनुसार कक्षा V और कक्षा VIII में पढ़ने का स्तर 2014, 2016, 2018, 2022, 2024

वर्ष	कक्षा V के उन बच्चों का % जो कक्षा II स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं			कक्षा VIII के उन बच्चों का % जो कक्षा II स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं		
	सरकारी	निजी	सरकारी और निजी*	सरकारी	निजी	सरकारी और निजी*
2014	42.2	62.6	48.0	71.5	82.4	74.7
2016	41.7	63.0	47.9	70.0	81.0	73.1
2018	44.2	65.1	50.5	69.0	82.9	73.0
2022	38.5	56.8	42.8	66.2	80.0	69.6
2024	44.8	59.3	48.8	67.5	80.0	71.1

*यह केवल सरकारी और निजी विद्यालयों में नामांकित बच्चों का भारित औसत है।

Table 1

तकनीकी असमानता

भारत में प्राथमिक शिक्षा में तकनीकी असमानता एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। शहरी इलाकों में तो स्कूलों में इंटरनेट, स्मार्ट बोर्ड और कंप्यूटर जैसी सुविधाएँ हैं, लेकिन कई ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में तो बुनियादी सुविधाएँ भी नहीं हैं। इससे बच्चों को पढ़ाई में सही तरीके से मदद नहीं मिल पाती। कई बार डिजिटल उपकरणों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता, जिससे उनकी पढ़ाई पर सीधा असर पड़ता है।

पाठ्यक्रम की अपेक्षाकृत कम प्रासंगिकता

भारत में प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बहुत बार बच्चों की असल जिंदगी में व्यावहारिक रूप से मेल नहीं खाता। कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि जो सिखाया जा रहा है, वह उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और उनके भविष्य के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, ऐसे में उनकी रूचि कम होने लगती है। इसके अलावा, पाठ्यक्रम में स्थानीय और सांस्कृतिक पहलुओं की कमी है, जिससे बच्चों को समझने में दिक्कत आती है। इसलिए जरूरी है कि पाठ्यक्रम को समय-समय पर अपडेट किया जाए, ताकि वह बच्चों की ज़रूरतों से मेल खा सके।

विकसित भारत में योगदान हेतु प्राथमिक शिक्षा में आवश्यक सुधार

बुनियादी संरचना में सुधार

भारत में प्राथमिक शिक्षा को सही मायनों में मजबूत करना है तो स्कूलों की बुनियादी चीज़ें ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अबी भी कई स्कूल ऐसे है जहाँ बच्चे बिना पंखे के पढ़ते हैं, और कभी-कभी जर्जर और पुरानी छत के निचे बैठ के पढ़ते हैं। शौचालय नहीं होते, पीने का साफ पानी नहीं, और बिजली का भी भरोसा नहीं होता। ऐसे में कोई भी बच्चा पढ़ाई में मन कैसे लगाएगा? जब सुविधाएँ अधूरी हों तो अध्यापक को भी समस्या होती है। शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने तथा उसकी पहुँच को सर्वसुलभ बनाने के लिए सरकार भी सतत रूप से प्रयासरत रहती है। सर्व शिक्षा अभियान के सन्दर्भ में **मदनलाल**[2] का शोध बताता है कि, सर्वशिक्षा अभियान के तहत पाठ्यक्रम विकास का विद्यालय स्तर पर प्रभावी केन्द्रीकरण किया गया है। इस बात से 84 प्रतिशत शिक्षक सहमत है।

शिक्षक गुणवत्ता और प्रशिक्षण में निवेश

भारत में प्राथमिक शिक्षा की नींव शिक्षक ही होते हैं। एक अच्छा शिक्षक सिर्फ पढ़ाता नहीं, बच्चों में सोचने और समझने की आदत भी डालता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें ठीक से ट्रेनिंग ही नहीं मिली होती, या वो पुराने तरीकों से ही पढ़ाते रह जाते हैं। देश नवाचार की ओर बढ़ रहा है इसलिए बच्चों को पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा नया होना चाहिए। इसके लिए शिक्षक प्रशिक्षण पर और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों में नवाचार

आज भी कई स्कूलों में वही पुराना सा रटा-रटाया तरीका चलता है, जिससे बच्चा सिर्फ याद करता है, समझता नहीं। थोड़ा इनोवेशन ज़रूरी है, जैसे गेम्स के ज़रिए पढ़ाना, छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स देना या फिर डिजिटल उपकरण इस्तेमाल करना। और हाँ, जो बच्चे जिस इलाके से आते हैं, उनके माहौल के हिसाब से चीज़ें जोड़नी भी ज़रूरी है। जब पढ़ाई अपने आस-पास से जुड़ती है, तब ही वो दिल से लगती है। **कार्तिक मुरलीधरन** बताते हैं कि, प्राथमिक शिक्षा में 'सामान्य रूप से व्यवसाय' तरीके से इनपुट बढ़ाने से छात्रों के सीखने में सार्थक तरीके से सुधार होने की संभावना नहीं है, जब तक कि शिक्षणशास्त्र में महत्वपूर्ण बदलाव और/या स्कूल प्रशासन में सुधार न हो।[3]

डिजिटल समावेशन (Digital Inclusion)

भारत में अगर प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाना है तो डिजिटल समावेशन बेहद जरूरी है। हर बच्चे के पास अब ये मौका होना चाहिए कि वो तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई को और रोचक बना सके। खासकर उन इलाकों में, जहाँ बच्चों को स्मार्ट क्लास या इंटरनेट जैसी चीज़ें नहीं मिल पातीं। अगर शिक्षकों एवं बच्चों को डिजिटल चीज़ों का सही इस्तेमाल सिखाया जाए, तो ना केवल उनकी पढ़ाई बेहतर होगी, बल्कि वो भविष्य के लिए तैयार भी होंगे। इस सन्दर्भ में **जननी गणपति**[4] का विचार है कि, मुक्त शिक्षा संसाधन open educational resources (OER) का उपयोग विभिन्न सांस्कृतिक और भाषाई सेटिंग्स में, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अधिक वितरण और पैमाने की अनुमति देता है, वे उन समाजों में इसके अनुकूलन और शैक्षणिक बाधाओं के खिलाफ भी चेतावनी देते हैं जहां पारंपरिक शिक्षा के तरीके स्थापित और विश्वसनीय हैं।

भाषा और समावेशिता को बढ़ावा

भारत में प्राथमिक शिक्षा में भाषा और समावेशिता को बढ़ावा देना बेहद ज़रूरी है। हमारे देश में इतनी सारी अलग-अलग भाषाएँ हैं, और हर बच्चा अपनी ही भाषा में सबसे अच्छा समझ पाता है। इसलिए, शिक्षा में हर बच्चे को अपनी मातृभाषा में सीखने का मौका मिलना चाहिए। बस, यही नहीं, समावेशिता का मतलब ये भी है कि जिन बच्चों को शारीरिक या मानसिक चुनौतियाँ हैं, उन्हें भी समान शिक्षा मिलनी चाहिए। जब बच्चों को अपनी भाषा में और अपने हालात के हिसाब से शिक्षा मिलेगी, तो वो ना सिर्फ सीख पाएंगे, बल्कि आत्मविश्वास से भरे होंगे। **परमजीत कौर**[5] शोध बताता है कि, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की सिफारिशों का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता का विकास करना है। मातृभाषा को उचित स्थान देकर भाषाई समस्या का समाधान करना, छात्रों के अध्ययन के प्रति रूचि का विकास करना। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। इसमें सकारात्मक कदम उठाये गये हैं।

सामुदायिक भागीदारी और अभिभावक सहभागिता

प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ में सामुदायिक भागीदारी और अभिभावक की भूमिका काफी अहम हो जाती है। जब माता-पिता स्कूल की गतिविधियों में शामिल होते हैं और समुदाय भी मिलकर काम करता है, तो बच्चों की शिक्षा में बहुत फर्क पड़ता है। अगर अभिभावक स्कूल में खुद को सक्रिय रखें, तो बच्चों के सीखने में भी अच्छा असर आता है। और हाँ, जब समुदाय का सहयोग मिलता है तो स्कूलों को अच्छे संसाधन और सुविधाएँ भी मिल सकती हैं।

मूल्य आधारित और नैतिक शिक्षा

भारत में प्राथमिक शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बच्चों को नैतिकता और अच्छे संस्कार भी सिखाने की जरूरत है। जब छोटे बच्चों को सत्य, अहिंसा, सहनशीलता जैसे मूल्य सिखाए जाते हैं, तो उनका व्यक्तित्व और भी मजबूत बनता है। इसके अलावा, ये भी जरूरी है कि बच्चे समाज के प्रति जिम्मेदार बने, ताकि वो बड़े होकर अच्छे नागरिक बन सकें।

विकसित भारत में प्राथमिक शिक्षा का संभावित स्वरूप

हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुँच

विकसित भारत में प्राथमिक शिक्षा का ये रूप होना चाहिए कि हर बच्चे तक अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचे। चाहे बच्चा शहरी इलाके का हो या फिर किसी दूरदराज गाँव का, हर किसी को समान अवसर मिलें। इसके लिए स्कूलों में अच्छे शिक्षक, बेहतर सुविधाएँ और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल होना जरूरी है। डिजिटल साधनों का भी फायदा उठाना चाहिए, ताकि हर बच्चे को उसकी जरूरत के हिसाब से शिक्षा मिल सके। सरकारी और निजी स्कूलों में फर्क न हो, और हर बच्चा अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार सही शिक्षा पा सके।

डिजिटल रूप से सशक्त स्कूल

विकसित भारत में प्राथमिक शिक्षा को डिजिटल रूप से सशक्त स्कूलों की ज़रूरत है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और ऑनलाइन स्टडी के अच्छे साधन होने चाहिए, ताकि बच्चों को पढ़ाई में कोई परेशानी ना हो। इससे बच्चे नई टेक्नोलॉजी से भी कनेक्ट हो सकेंगे। टीचर्स को भी इन डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल अच्छे से सिखाया जाएगा, ताकि वो बच्चों को और बेहतर तरीके से समझा सकें। बच्चों को कम्प्यूटर, इंटरनेट जैसे साधनों का सही इस्तेमाल भी सिखाया जाएगा, ताकि वे आने वाले समय के लिए तैयार हो सकें और तकनीकी दुनिया का सही इस्तेमाल कर सकें।

बहुभाषी और मातृभाषा-आधारित शिक्षण

विकसित भारत में प्राथमिक शिक्षा का मॉडल बहुभाषी और मातृभाषा-आधारित होना चाहिए। बच्चों को अगर उनकी अपनी मातृभाषा में पढ़ाया जाए, तो वो आसानी से समझ पाते हैं और सीखने में मज़ा आता है। इसके अलावा, जब हम बहुभाषी शिक्षा की बात करते हैं, तो बच्चों को कई भाषाओं के बीच संतुलन बनाने का मौका मिलता है, जिससे भविष्य में उन्हें बहुत फायदे मिलते हैं।[6] मातृभाषा में पढ़ाई से बच्चे जल्दी समझ पाते हैं और उनका दिमाग भी खुलता है। इस तरह की शिक्षा प्रणाली बच्चों के मानसिक विकास को बेहतर बनाएगी।

शिक्षकों का सशक्तिकरण

विकसित भारत में प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षक का सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। जब शिक्षकों को सही प्रशिक्षण, संसाधन और सम्मान मिलता है, तब वे बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा पाते हैं। उन्हें नई शैक्षिक विधियों और तकनीकों के बारे में जानकारी देना चाहिए। साथ ही, कक्षा में उन्हें कुछ रचनात्मक तरीके अपनाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यह भी जरूरी है कि शिक्षकों को समाज में उचित मान-सम्मान मिले, ताकि वे अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध रहें और बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने में पूरी तरह से जुड़े रहें।

समावेशी शिक्षा प्रणाली

विकसित भारत में प्राथमिक शिक्षा पूरी तरह से समावेशी होनी चाहिए, ताकि हर बच्चे को समान अवसर मिल सके। इसमें विशेष जरूरत वाले बच्चे, जैसे दिव्यांग बच्चे, को भी बराबरी की शिक्षा मिले। समावेशी शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि बस पढ़ाई हो, बल्कि हर बच्चे को उसकी क्षमता और जरूरत के हिसाब से शिक्षित किया जाए। स्कूलों में सभी सुविधाएं और संसाधन बच्चों को अच्छे से शिक्षा देने के लिए मौजूद हो, ताकि कोई बच्चा पीछे न रहे। इसके लिए टीचर्स को खास ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि हर बच्चे को ध्यान से पढ़ाया जा सके।

मूल्य, जीवन कौशल और नवाचार पर आधारित पाठ्यक्रम

विकसित भारत में प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों को जीवन जीने के लिए जरूरी मूल्य, जीवन कौशल और नवाचार की शिक्षा भी उपलब्ध होनी चाहिए।[7] बच्चे अगर सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छे होंगे, तो उनका विकास अधूरा रहेगा। इसलिए उन्हें ऐसी क्षमताएँ सिखानी चाहिए, जैसे समय का प्रबंधन, टीम में काम करना, समस्याओं का हल निकालना और आलोचनात्मक सोच, ताकि वे हर परिस्थिति का सही तरीके से सामना कर सकें। इसके साथ ही, नवाचार पर आधारित पाठ्यक्रम बच्चों को रचनात्मकता की ओर प्रेरित करेगा, जिससे वे खुद में नयापन लाने की क्षमता विकसित कर सकेंगे।

स्थानीय समुदाय और अभिभावकों की भागीदारी

विकसित भारत में प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए स्थानीय समुदाय और अभिभावकों की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है।[8] जब समुदाय और अभिभावक मिलकर बच्चों की शिक्षा में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो यह बच्चों के समग्र विकास में सहायक होता है। अभिभावक अगर शिक्षा प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो उनका योगदान बच्चों के प्रदर्शन पर सीधा असर डालता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुपस्थिति की भी समस्या है। **सिंह, राजेश कुमार** का अध्ययन बताता है कि, "इन क्षेत्रों में छात्रों की उपस्थिति अनियमित रहती है, उन्हें बुआई और कटाई के समय अस्थायी रूप से विद्यालयों से हटा दिया जाता है। अनियमित उपस्थिति के कारण यह छात्र विद्यालय के काम में पिछड़ जाते हैं और या तो वे अनुत्तीर्ण हो जाते हैं या विद्यालय छोड़ देते हैं"।[9] जनसमुदाय की भूमिका के सन्दर्भ में **पूनम सिंह** का सुझाव है कि, "प्राथमिक शिक्षा के विकास में जनसमुदाय की अहम् भूमिका होती है। जनसमुदाय में शिक्षा के प्रति जागृति पैदा करने हेतु सचल दल गठित करने की आवश्यकता है जो विभिन्न माध्यमों से शिक्षा का प्रचार व प्रसार करें"[10]।

निष्कर्ष एवं सुझाव

जब हम भारत में प्राथमिक शिक्षा की आज की स्थिति को देखतें हैं, तो ऐसा लगता है कि एक तरफ हमने बहुत कुछ हासिल किया है, जैसे ज़्यादा बच्चे स्कूल आ रहे हैं, योजनाएं चल रही हैं, और स्कूलों की गिनती भी बढ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी अधूरा सा लगता है। जैसे- क्या हर बच्चा स्कूल में जाकर सच में सीख रहा है? क्या उसे वो माहौल मिल रहा है जहाँ वो खुल कर सोच सके, समझ सके? शायद नहीं, क्योंकि अब भी बहुत सी जगहों पर स्कूलों एवं शिक्षकों की हालत ठीक नहीं है। जब हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, तो यह जरूरी हो जाता है कि हम ये सोचें कि उस समय की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। शायद ऐसी, जहाँ पढ़ाई सिर्फ किताबों में सिमटी न हो, बल्कि बच्चे टेक्नोलॉजी से, जीवन कौशल से और नैतिक मूल्यों से भी जुड़े रहें। और वे अपनी भाषा में समझे और सवाल पूछना सीखे, न कि चुपचाप बैठे रहे।

बात आती है कि आज की शिक्षा में क्या बदलाव लाएं ताकि वो कल के भारत को बेहतर बना सके। इसका जवाब आसान नहीं है, पर कुछ बातें साफ हैं, जैसे टीचर्स को लगातार ट्रेनिंग मिलती रहे, स्कूलों में साफ पानी, बिजली और डिजिटल साधन हों, और पढ़ाई ऐसी हो जो सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, ज़िंदगी के लिए भी हो। कुल मिलाकर, अगर हमें सच में 2047 तक एक विकसित भारत बनाना है, तो उसकी शुरुआत आज के स्कूलों से करनी होगी। हम बच्चों को सिर्फ ज्ञान नहीं, सोचने की आज़ादी, कोशिश

करने का हौसला और समाज को समझने की समझ दें। तभी तो वो बड़े होकर न सिर्फ नौकरी के लायक, बल्कि एक ज़िम्मेदार नागरिक भी बन सकेंगे। और शायद तब हम गर्व से कह पाएंगे कि "हमने वाकई एक विकसित भारत बनाया है"।

सन्दर्भ

1. UDISE_Report_2023_24_NEP_Structure, Page- 9, https://udiseplus.gov.in/#/en/page/publications

2. मदनलाल (2009). राजस्थान राज्य में प्राथमिक शिक्षा के विकास में सर्व शिक्षा अभियान की भूमिका का अध्ययन (हनुमानगढ़ जिले के सन्दर्भ में). अप्रकाशित लघु-शोधप्रबन्ध. महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, पृष्ठ- 86, https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/289531

3. Karthik Muralidharan (2013). Priorities for Primary Education Policy in India's 12th Five-year Plan, https://pdel.ucsd.edu/_files/paper_2013_karthik.pdf

4. janani Ganapathi (2018). Open Educational Resources: Challenges and Opportunities in Indian Primary Education. International Review of Research in Open and Distributed Learning. Volume 19, Number 3, https://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/3662/4651

5. कौर, परमजीत (2023). शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का अध्ययन : प्राथमिक शिक्षा के विशेष सन्दर्भ में. अप्रकाशित शोधप्रबन्ध. शिक्षाशास्त्र विभाग, मेवाड़ विश्वविद्यालय राजस्थान. पृष्ठ- 176, https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/619743

6. https://www.cheggindia.com/hi/nayi-shiksha-neeti-2020/

7. https://hindiparenting.firstcry.com/articles/speech-on-education-in-hindi/

8. https://www.samareducation.com/2022/04/meaning-development-and-objectives-of-primarye-ducation-in-hindi.html

9. सिंह राजेश कुमार (2005). वाराणसी जनपद में प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं समस्याओं का अध्ययन. अप्रकाशित शोध-प्रबन्ध. शिक्षाशास्त्र विभाग, हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी. पृष्ठ- 180, https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/171179

10. सिंह पूनम (2002). भदोहीं जनपद में प्राथमिक शिक्षा के विकास का समालोचनात्मक अध्ययन. अप्रकाशित शोधप्रबन्ध. शिक्षा संकाय. वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर. पृष्ठ- 175, https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/179090